दैनिक
लोक टुडे
जनता की आवाज...
विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 323 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | सोमवार 08 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

प्रवासी मजदूरों, छात्रों और अकेले रहने वाले कामगारों को बड़ी राहत

अब पेट्रोल पंप पर मिलेगा 5 किलो का 'छोटू सिलेंडर'

गैस कनेक्शन के लिए नहीं काटने होंगे एजेंसियों के चक्कर, रसोई गैस की रीफिलिंग भी हुई आसान

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान सहित पूरे देश में रसोई गैस उपभोक्ताओं, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों, छात्रों और अकेले रहने वाले कामगारों के लिए राहत की बड़ी खबर है। तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने आमजन की सुविधा के लिए अब पेट्रोल पंपों, अधिकृत खुदरा किराना दुकानों और स्थानीय वितरकों पर 5 किलो का 'छोटू सिलेंडर' आसानी से उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनके पास स्थानीय पते का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता और वे भारी-भरकम कागजी कार्रवाई के कारण गैस कनेक्शन लेने से कतराते हैं।

बिना एड्रेस प्रूफ के सिर्फ ID दिखाते ही मिलेगा कनेक्शन -

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी नागरिक केवल अपना एक वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड) दिखाकर काउंटर से सीधे नया छोटू सिलेंडर खरीद सकता है। यह पूरी तरह से फ्री ट्रेड एलपीजी मॉडल पर आधारित है, जिससे उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के चक्कर काटने और लंबी प्रतीक्षा सूची से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी।

एड्रेस प्रूफ की भी जरूरत नहीं !

रीफिलिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम -

तेल विपणन कंपनियों के अनुसार, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इन सिलेंडरों को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह सिलेंडर लीक-प्रूफ और उठाने में बेहद हल्के हैं, जिससे इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है। खाली होने पर उपभोक्ता अपने नजदीकी किसी भी अधिकृत पेट्रोल पंप, इंडेन या अन्य डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर जाकर खाली सिलेंडर देकर तुरंत दूसरा भरा हुआ सिलेंडर ले सकेंगे।

कम बजट और आपातकाल के लिए बेहतरीन विकल्प -

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम उन छोटे कामगारों और कम आय वर्ग वाले परिवारों के लिए बेहद मददगार साबित होगा, जो एक साथ 14.2 किलो का बड़ा और महंगा घरेलू सिलेंडर खरीदने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, जिन घरों में अचानक बड़ा घरेलू सिलेंडर खत्म हो जाता है, उनके लिए भी यह 'छोटू सिलेंडर' एक बेहतरीन और तत्काल मिलने वाले बैकअप विकल्प के रूप में काम करेगा।

घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी, नई रेट लागू

राजस्थान में आमजन को महंगाई का फिर झटका लगा है। तेल-गैस कंपनियों ने घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में देर रात बढ़ोतरी की है, जिसे रविवार से लागू किया गया है। रिव्यू की गई कीमतों में 14 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर पर 29 रुपए की बढ़ोतरी की है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया- कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, जिसकी नई रेट लिस्ट जारी की है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक, जयपुर में रविवार से 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर 916.50 के बजाए 945.50 रुपए में बाजार में मिलेंगे। वहीं 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर 341.50 के बजाए 352 रुपए में मिलेंगे। जबकि 10 किलोग्राम वाले कम्पोजिट सिलेंडर (प्लास्टिक बॉडी वाले) 655 रुपए के बजाए 675 रुपए में मिलेंगे। सिलेंडरों की कीमतों की गई यह बढ़ोतरी लागू कर दी गई है।

राहुल बोले- 18 साल का सार्थक सीबीआई से तेज निकला

नई दिल्ली

18 साल के सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई की 12वीं क्लास के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली और OSM का काम करने वाली कंपनी COEMPT से जुड़ी टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी का खुलासा किया है। राहुल ने कहा,

देश का 18 साल का युवा CBI से तेज निकला, नौजवानों की ये जीत सही मायने में सरकार की हार है।

झारखंड के रांची के रहने वाले सार्थक ने भी इस साल 12वीं के एग्जाम दिए थे। नंबर कम आने पर उन्होंने री-इवैल्यूएशन के लिए अपनी स्कैन की गई आंसरशीट मंगाई थीं।

गलत नंबर कटने और दूसरी परेशानियों को सार्थक ने सोशल मीडिया पर शेयर था। सार्थक CBSE में सुधार के लिए संसद की स्थायी समिति के सामने 500 पेज की प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं।

राहुल: यह अच्छा है या बुरा, आप इस पर क्या सोचते हैं।

सार्थक: मैंने वही किया जो नागरिक को किसी भी चीज को लेकर करना चाहिए। ये हमारा देश है हर किसी में इतना सिविक सेंस जरूर होना चाहिए कि चीजों को पढ़कर सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काम करे। चाहें कितनी भी गड़बड़ी हो, लेकिन सुधार के लिए काम करना चाहिए।

राहुल: जो हुआ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?

सार्थक: निसर्ग अधिकारी एथिकल हैकर है। उसने मुझे ग्रुप चैट पर ह्रस्रू पोर्टल की गड़बड़ी शेयर की। मैंने देखा तो पाया कि उसमें सबकुछ ऑनमार्क द्वारा किया गया था। ऑनमार्क ह्रस्रू इवैल्यूएशन के लिए एडटेक सॉल्यूशन कंपनी है। मैंने इसके बारे में और पता लगाया। निसर्ग ने मुझे दूसरी यूनिवर्सिटीज की भी डिटेल भेजी, जो ऑनमार्क का यूज करती थीं। उनमें भी गड़बड़ी दिखी। इसके बाद मुझे लगा कि सीबीएसई क्यों ऐसी कंपनी का यूज कर रही है, जिसके साथ इतनी गड़बड़ियां जुड़ी हैं। राहुल: 18 साल का लड़का लूपहोल ढूंढ सकता है, तो ये बड़ा सिस्टम क्यों नहीं?

सार्थक: मुझे लगता है कि ये लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। 3 बार टेंडर बदला गया, रुल्स बदले गए, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट COEMPT एडुटेक को दिया गया। गड़बड़ी की बात सामने आने पर भी जांच नहीं की गई, रुल्स बार-बार बदले गए। हो सकता है कि उन्हें को कंपनी ज्यादा पसंद हो या उन्हें हम 17 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर की चिंता नहीं हो।

जयपुर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित

जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 08 जून 2026 को प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।

संभागीय आयुक्त, जयपुर वी सरवन कुमार ने आदेश जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं इंटरनेट आधारित सेवाओं के दुरुपयोग से अफवाहों के प्रसार तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आदेशानुसार पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अधीन गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आदर्श नगर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जलूपुरा, संजय सर्किल, शास्त्रीनगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर, जयसिंहपुरा खोर, बनीपार्क, कानोता, तूंगा, आंधी, जमवारामगढ़, सामोद, रायसर, गोविंदगढ़, चंदवाजी, शाहपुरा, अचरोल, विराटनगर, पावटा, प्रागपुरा, मनोहरपुर, भाबरू, कालाडेरा, चौमूं, हरमाड़, झोटवाड़ा, करधनी, वैशाली नगर, सोडाला, श्याम नगर, गांधी नगर, बजाज नगर, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, सांगानेर, प्रतापनगर, मुहाना, शिवदासपुरा, बगरू, दूदू, फागी तथा फुलेरा सहित जयपुर उत्तर एवं जयपुर पूर्व जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 08 जून 2026 की रात्रि 12:00 बजे से 09 जून 2026 की रात्रि 12:00 बजे तक 2ल, 3ल, 4ल एवं 5ल मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) सहित अन्य सोशल मीडिया सेवाएं निलंबित रहेंगी। हालांकि वॉयस कॉल सेवाएं पूर्ववत संचालित रहेंगी।

प्रशासन ने आमजन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा आदेशों की पालना करने की अपील की है। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का दावा

अखिलेश बोले- सरकार की चुप्पी संदिग्ध; चंपत राय ने कहा- कोई गड़बड़ी नहीं मिली

अयोध्या/लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी की गई है। उन्होंने रविवार दोपहर ङ्क पोस्ट लिखकर कहा, सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए।

अयोध्या में सपा के पूर्व विधायक व मंत्री रहे पवन पांडेय ने दावा किया कि 5 से साढ़े 7 करोड़ तक की चोरी की गई है। अगर चोरी नहीं हुई है तो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आएं और प्रभु श्रीराम की कसम खाकर कहें कि आरोप झूठे हैं। अगर बात सच है तो एफआईआर करवाएं।

अखिलेश के आरोपों पर चंपत राय ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, ट्रस्ट का समय-समय पर आंतरिक ऑडिट होता है। इस काम में ट्रस्ट और बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। ऑडिट कई दिन तक चलता है। वही काम आजकल हो रहा है। अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है।

अखिलेश ने लिखा- रुपए गायब होना मंदिर ट्रस्ट के लिए शर्मनाक

अखिलेश ने एक्स पोस्ट कर लिखा,

पूरी दुनिया में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील खबर है। राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब मिली है। अखिलेश ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सरकार को भी घेरा है। लिखा, करोड़ों रुपए गायब होना मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। सपा अध्यक्ष ने कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने की मांग की है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनानती समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। पवन पांडेय सपा सरकार में वन और मनोरंजन कर राज्य मंत्री रहे हैं। दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अयोध्या राम मंदिर के अंदर जो दानपात्र रखे हुए हैं, जो चढ़ावा आता है, उसमें 5 से 7.50 करोड़ तक की चोरी की गई है। इसमें भाजपा के ही कार्यकर्ताओं के और ट्रस्ट के कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। मैं इस देश की सरकार और यूपी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे? क्या उन चोरों पर एफआईआर होगी? क्योंकि देश के करोड़ों लोगों की आस्था उस मंदिर से जुड़ी हुई है। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा, एक-एक रुपया जोड़कर उस मंदिर के निर्माण के लिए और भगवान राम के चरणों में अर्पित किया था। अगर वहां इस तरह की चोरी हो रही है, तो यह बहुत ही निंदनीय है। सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो भी दोषी हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। उन्होंने कहा, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये चोरी कितने समय से हो रही थी। ट्रस्ट के किन-किन सदस्यों तक ये पैसा गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान जल आत्मनिर्भरता की ओर से तेजी से अग्रसर

वागड़ अंचल के लिए मील का पत्थर होगी अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना

जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा 'अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना' को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए युद्धस्तर पर कार्य करवाए जा रहे हैं। वागड़ अंचल के किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रही इस परियोजना से जनजाति बहुल क्षेत्र में कृषि व्यवस्था एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

लगभग 2 हजार 500 करोड़ रुपए लागत की परियोजना से बांसवाड़ा जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों (बांसवाड़ा, बागीदौरा एवं कुशलगढ़) की 6 तहसीलों बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, आनंदपुरी एवं गांगड़तलाई के 338 गांवों की लगभग 42 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध होगा। परियोजना से लगभग 3.5 लाख आबादी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी।

102 किमी मुख्य नहर लम्बाई, 22.50 किमी सुरंगें

परियोजना में आधुनिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से नहर नेटवर्क एवं विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना की कुल मुख्य नहर लंबाई 102 किलोमीटर है। इसमें 22.50 किलोमीटर लंबाई में सुरंगे/कट एंड कवर संरचनाएं, एक्वाडक्ट तथा नदी को पार करते हुए साइफन निर्मित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 230 अन्य नहरी महत्वपूर्ण संरचनाए यथा सुपरपासेज, ड्रेनेज साइफन, रोड ब्रिज, एस्केप कम क्रॉस रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर इत्यादि भी परियोजना में शामिल हैं।

प्रेशर प्रणाली आधारित कमांड क्षेत्र होगा विकसित

परियोजना के तहत अत्याधुनिक प्रेशर प्रणाली आधारित कमांड क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इससे खेत तक वैज्ञानिक एवं नियंत्रित सिंचाई स्काड़ा प्रणाली से सुनिश्चित हो सकेगी। सिंचित क्षेत्र में प्रत्येक 200 हेक्टेयर के 'चक स्तर' पर लगभग 200 डिग्गियों का निर्माण प्रस्तावित है। मुख्य नहर प्रणाली से इन डिग्गियों तक पानी एमएस व डीआई पाइपलाइन पहुंचाया जाएगा। इसके बाद डिग्गियों से लगभग 5 हजार कि.मी. लंबाई का भूमिगत एचडीपीई पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे प्रेसराइज्ड इरिगेशन प्रणाली से खेतों तक पानी पहुंचेगा। इस आधुनिक सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक लगभग 1.25 से 1.50 हेक्टेयर क्षेत्र पर हाइड्रेंट विकसित किए जाएंगे। इन हाइड्रेंट पॉइंट्स तक भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क बिछेगा, जहां से किसान सीधे सिंचाई के लिए जल प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रणाली से खेत स्तर तक समान जल वितरण, न्यूनतम जल हानि तथा अधिक दक्ष सिंचाई सुनिश्चित होगी। आधुनिक माइक्रो एवं प्रेसराइज्ड इरिगेशन प्रणाली के जरिए कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव हो सकेगी। किसानों को निरंतर बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

स्काडा प्रणाली से ऑटोमाइज होगी मॉनिटरिंग

परियोजना में अत्याधुनिक स्काड़ा (पर्यवेक्षक नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) प्रणाली भी विकसित की जा रही है। इससे सम्पूर्ण प्रेशर प्रणाली आधारित तंत्र का संचालन एवं मॉनिटरिंग पूर्णत: ऑटोमाइज्ड होगी। इस प्रणाली से जल वितरण को समान रूप से सुनिश्चित करने, दबाव एवं प्रवाह को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने तथा रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग एवं संचालन नियंत्रण की सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रणाली से पम्पिंग स्टेशन, रिलीफ वाल्व, हाइड्रेंट एवं विभिन्न शाखाओं में जल प्रवाह की सतत निगरानी संभव होगी। वर्तमान में नहर की 42 किलोमीटर में काम किया जा रहा है। इनटेक स्ट्रक्चर एवं स्लूइस बैरल का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। टनल कार्य, एक्वाडक्ट, साइफन, कट एंड कवर के साथ नहर से डिग्गी तक भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क निर्माण कार्य भी विभिन्न स्थानों पर निरंतर जारी है।

नियमित मॉनिटरिंग से मिली गति

परियोजना की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। समयबद्ध और पारदर्शिता से कार्यों को पूर्ण करने के लिए निर्माण एजेंसियों को विभागीय निर्देश दिए गए हैं। इस परियोजना के लिए 78 गांवों की लगभग 270 हेक्टेयर निजी भूमि का नियमानुसार अधिग्रहण किया जा रहा है। अब तक 67 गांवों की 211 हेक्टेयर भूमि के लिए लगभग 47 करोड़ रुपए राशि के अवार्ड पारित हो चुके हैं। लगभग 15 करोड़ रुपए मुआवजा राशि वितरित की गई है। शेष अधिग्रहण एवं वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रियाएं भी तेजी से हो रही हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि आगामी वर्षों में यह परियोजना बांसवाड़ा जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में शामिल होगी। इसके पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के किसानों को वर्षभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन एवं बागवानी फसलों का रकबा बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इससे भू-जल स्तर सुधार, जल संरक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही, यह परियोजना वागड़ क्षेत्र के जनजाति बहुल इलाकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

मिलावट-मुक्त भारत से ही विकसित भारत संभव

ललित गर्ग

ारत में मिलावट का कारोबार आज एक संगठित आर्थिक अपराध का रूप ले चुका है। दूध में डिटर्जेंट, यूरिया और सिंथेटिक रसायनों का प्रयोग, मावे में स्टार्च और रासायनिक पदार्थों की मिलावट, मसालों में रंग और धूल, शहद में चीनी सिरप, खाद्य तेलों में सस्ते तेलों का मिश्रण तथा फलों और सब्जियों को कृत्रिम रसायनों से पकाना आम बात हो गई है। बाजार में बिकने वाले अनेक उत्पाद देखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन भीतर से विषैले सिद्ध होते हैं। स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब दवाइयों में मिलावट या नकली दवाओं का मामला सामने आता है।

हर वर्ष 7 जून को मनाया जाने वाला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस केवल सुरक्षित भोजन की आवश्यकता का स्मरण कराने वाला दिवस नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, आर्थिक समृद्धि और सतत विकास के लिए एक वैश्विक संकल्प का अवसर भी है। वर्ष 2026 की थीम 'खाद्य सुरक्षाः विज्ञान की सक्रिय भूमिका' इस बात पर बल देती है कि विज्ञान, अनुसंधान, तकनीक और प्रभावी निगरानी प्रणालियों के माध्यम से ही सुरक्षित खाद्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन विडम्बना यह है कि भारत जैसे विशाल कृषि प्रधान देश में खाद्य पदार्थों, दवाइयों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं में बढ़ती मिलावट इस लक्ष्य को गंभीर चुनौती दे रही है। मिलावट केवल खाद्य सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्र के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, नैतिकता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है। जिस देश को विश्वगुरु और विकसित भारत बनने का सपना है, वहां यदि दूध, घी, मावा, मसाले, अनाज, मिठाइयां, फल-सब्जियां और यहां तक कि जीवनरक्षक दवाइयां भी मिलावट की शिकार हों, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवता के विरुद्ध अपराध है।

भारत में मिलावट का कारोबार आज एक संगठित आर्थिक अपराध का रूप ले चुका है। दूध में डिटर्जेंट, यूरिया और सिंथेटिक रसायनों का प्रयोग, मावे में स्टार्च और रासायनिक पदार्थों की मिलावट, मसालों में रंग और धूल, शहद में चीनी सिरप, खाद्य तेलों में सस्ते तेलों का मिश्रण तथा फलों और सब्जियों को कृत्रिम रसायनों से पकाना आम बात हो गई है। बाजार में बिकने वाले अनेक उत्पाद देखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन भीतर से विषैले सिद्ध होते हैं। स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब दवाइयों में मिलावट या नकली दवाओं का मामला सामने आता है। पिछले वर्षों में विभिन्न राज्यों में नकली अथवा घटिया दवाओं के सेवन से अनेक लोगों की मृत्यु और गंभीर स्वास्थ्य संकट की घटनाएं सामने आईं। राजस्थान के कोटा सहित कई स्थानों पर ऐसी खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। जब जीवन बचाने वाली दवा ही मौत का कारण बनने लगे, तब यह केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

मिलावट का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। कैंसर, किडनी रोग, हृदय रोग, यकृत संबंधी विकार, हार्मोन असंतुलन, बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याएं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसी अनेक गंभीर समस्याओं का संबंध दूषित एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों से जुड़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार असुरक्षित भोजन के कारण हर वर्ष करोड़ों लोग बीमार पड़ते हैं। भारत में भी स्वास्थ्य पर पड़ने वाला यह बोझ लगातार बढ़ रहा है। किन्तु मिलावट का संकट केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रहार करता है। जब किसी देश के खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता संदिग्ध हो जाती है, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। निर्यात घटता है, विदेशी निवेश प्रभावित होता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश पिछड़ जाता है। भारत कृषि उत्पादों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक बड़ा केंद्र बन सकता है, लेकिन मिलावट की समस्या उसकी संभावनाओं पर ग्रहण लगा रही है।

इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि मिलावट सामाजिक मूल्यों के क्षरण का प्रतीक बनती जा रही है। कुछ लोग त्वरित लाभ और अधिक मुनाफे की लालसा में दूसरों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि नैतिक पतन का भी संकेत है। जब समाज में ईमानदारी और उत्तरदायित्व की भावना कमजोर पड़ती है, तब ऐसे अपराध फलने-फूलने लगते हैं। सरकारों ने समय-समय पर खाद्य सुरक्षा और मानक कानून बनाए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) सहित अनेक संस्थाएं निगरानी और परीक्षण का कार्य करती हैं। फिर भी जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, निरीक्षण तंत्र की कमजोरी और कानूनी प्रक्रियाओं की धीमी गति मिलावट के विरुद्ध अभियान को प्रभावी नहीं बनने देती। अनेक मामलों में दोषियों को दंड मिलने में वर्षों लग जाते हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं।

आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें कठोरता और पारदर्शिता के साथ लागू करने की है। खाद्य पदार्थों की नियमित जांच, आधुनिक प्रयोगशालाओं का विस्तार, डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली, त्वरित न्याय व्यवस्था और दोषियों के लिए कठोर दंड आवश्यक हैं। मिलावट को सामान्य आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य के विरुद्ध गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम विज्ञान की भूमिका पर जोर देती है। विज्ञान और तकनीक मिलावट के विरुद्ध सबसे प्रभावी हथियार बन सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन आधारित आपूर्ति श्रृंखला, आधुनिक परीक्षण तकनीक, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब तथा उपभोक्ता जागरूकता एप्लिकेशन खाद्य सुरक्षा को नई दिशा दे सकते हैं। वैज्ञानिक निगरानी से उत्पादन से लेकर उपभोग तक हर चरण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन केवल सरकार या विज्ञान ही इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। समाज और उपभोक्ताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जागरूक नागरिकों को संदिग्ध उत्पादों की शिकायत करनी चाहिए, प्रमाणित उत्पादों का उपयोग करना चाहिए तथा स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा के प्रति जनजागरण अभियान चलाने चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संगठनों को भी इस विषय को सामाजिक आंदोलन का रूप देना होगा।

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर यदि हम वास्तव में एक विकसित, स्वस्थ और सम्मानित भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो 'मिलावट-मुक्त भारत' को राष्ट्रीय अभियान बनाना होगा। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान ने जनभागीदारी से व्यापक परिवर्तन लाया, उसी प्रकार मिलावट के विरुद्ध भी राष्ट्रीय चेतना का निर्माण आवश्यक है। भारत की पहचान योग, आयुर्वेद, शुद्ध आहार, नैतिक जीवन-मूल्यों और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की संस्कृति से रही है। यह पहचान तभी सार्थक होगी जब हमारे भोजन, दवाइयों और उपभोग की वस्तुओं में शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो। एक ऐसा भारत, जहां भोजन विश्वास का प्रतीक हो, जहां दवा जीवन का संरक्षण करे, जहां व्यापार नैतिकता पर आधारित हो और जहां उपभोक्ता निश्चिंत होकर बाजार से वस्तुएं खरीद सके-वही विकसित भारत का वास्तविक स्वरूप होगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें यह संदेश देता है कि सुरक्षित भोजन केवल स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, बल्कि मानव गरिमा और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। यदि हम आज मिलावट के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष का संकल्प लें, तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध भारत दे सकते हैं। 'शुद्ध आहार, स्वस्थ परिवार, मिलावट-मुक्त भारत, विकसित भारत का आधार', यही 2047 के विकसित भारत की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा और यही विश्व समुदाय के समक्ष भारत को एक आदर्श राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा।

(लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

धीमे जहर के कारोबारी

यह इंसान के पतन की पराकाष्ठा ही है कि समाज में बच्चों, वृद्धों, बीमारों व कमजोर लोगों के स्वास्थ्यवर्धन हेतु डॉक्टर दूध-घी-फल लेने को कहे, लेकिन जब उन्हें ये मिले तो उसमें भारी मिलावट पायी जाए। लोग अस्पतालों में बीमारियों से जूझते अपने परिजनों को शीघ्र ठीक करने के लिये दूध व जूस आदि देते हैं, लेकिन उनमें भी यदि घातक रसायन मिले होंगे, तो वे कैसे ठीक हो सकते हैं?

पिछले दिनों राजस्थान से अलीगढ़ लाया जा रहा सैकड़ों किलो घी बरामद हुआ। हापुड़ में करीब 22 लाख का नकली शहद पकड़ा गया। सोमनाथ में किडनी-लीवर को नुकसान पहुंचाने वाला यूरिया, डिटर्जेंट व कास्टिक सोडा मिला तीन हजार लीटर दूध बरामद होने की खबरें मीडिया में तैरती रहीं। आखिर लोभी मनुष्य के पतन की कोई सीमा भी है? चंद रुपयों के मुनाफे के लिये हम अपना दीन-ईमान बेचने के लिये कैसे तैयार हो जाते हैं? जीवन रक्षक दवा से लेकर खानपान में मिलावट की लगातार आने वाली खबरें विचलित करती हैं कि क्या खाएं और क्या न खाएं। पहले कहा जाता था कि ऊपर वाले से डर के कह रहा हूं। लोगों में नैतिकता का भाव होता था। समाज में धारणा थी कि दूसरों के लिये कुंआ खोदने वाला खुद के लिये खाई खोद रहा होता है। लेकिन आखिर समाज में ऐसा क्या हुआ कि लोगों में दुनिया की रचना करने वाले का भय व लोककल्याण का भाव खत्म हो गया। निश्चय ही ये रामराज जैसा वक्त नहीं है। हर दौर में अच्छे-बुरे लोग होते ही हैं। नकारात्मक सोच व दूसरों को कष्ट देकर खुश होने वाले रुग्ण मानसिकता के लोग हर काल खंड में पाये जाते रहे हैं। लेकिन उनका प्रतिशत कम रहा है। आज तो हर व्यक्ति मुनाफे से रातों-रात धनी हो जाना चाहता है,अब चाहे किसी की जान भी जाए, उसकी बला से। निस्संदेह, ये घटनाएं किसी सभ्य के माथे पर कलंक जैसी ही हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि फलों को तुरत-फुरत पकाने वाले रसायनों का जमकर प्रयोग किया जा रहा है। हरी सब्जी व फलों को घातक रसायन से चमकदार बनाया जा रहा है। दरअसल, तुरंत फसल लेने के लिये ऐसे घातक रसायन प्रयोग किए जा रहे हैं, जिन पर तमाम सभ्य समाजों में पूर्ण प्रतिबंध है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नियामक तंत्र विकसित ही नहीं हो पाया है, जो ऐसे मामलों में तुरत-फुरत जांच करे और तत्काल मिलावटखोरों को सजा दिलाए। विडंबना यह भी है कि हमारे समाज में स्वयं सेवी संगठन या जागरूक लोग इस गंभीर संकट के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। शासन-प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि हर शहर में मिलावटी सामान की जांच करने वाली लैब की सहज उपलब्धता क्यों नहीं है? जिन विभागों के अधिकारियों के पास जांच-पड़ताल का दायित्व होता है, वे चुप क्यों रहते हैं? दीपावली व अन्य त्योहारों पर जनाक्रोश के चलते कुछ छोटे हलवाइयों पर कार्रवाई होती है, मगर बड़ी मछलियां साफ बच निकलती हैं। क्या इन अधिकारियों की खामोशी में चांदी के जूते की चोट शामिल होती है? यह किसी से नहीं छिपा कि ये मलाईदार पोस्ट कितने लेन-देन के बाद मिलती हैं। राजनेताओं से लेकर अधिकारियों तक को लेन-देन के बाद ही उनकी पांचों उंगलियां घी में होती है। फिर वे भी नियुक्ति में किए गए निवेश की वसूली में जुट जाते हैं। निश्चय ही एक कारगर तंत्र को विकसित किए बिना इस घृणित कारोबार पर लगाम लगना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि जब से देश में सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग बढ़ा है, लाखों सच सामने आए हैं। अन्यथा ये सच कभी अनावृत न होते। ऐसी ही कोई कारगर तकनीक मिलावट रोकेगी। जयपुर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले दिनों पैकेज्ड फूड आइटम्स पर लिखी एक्सपायरी डेट मिटाने वाले अत्याधुनिक उपकरण बरामद किए।

चिंतन-मनन

इच्छाएं जीवात्मा को मोह से बांधे रखती हैं

इंद्रियां, मन और बुद्धि काम-वासना के निवास-स्थान कहे जाते हैं। इनके द्वारा ज्ञान को ढककर काम-वासना जीवात्मा को मोहित करती है। कामरूपी दुश्मन का नाश करने के लिए यह पता होना जरूरी है कि यह रहता कहां है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि काम-वासना किसी एक जगह नहीं रहती, बल्कि यह तो हमारे तीनों शरीरों- स्थूल, सूक्ष्म और कारण में निवास करती है। इसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है, इसलिए इसका नाश करना बड़ा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर जब काम-वासना इन्द्रियों में जगती है, तब इन्द्रियां बेकाबू हो जाती हैं। जब यह मन में जगती है तो दूसरे काम करते हुए भी मन में काम-वासना के बारे में ही ख्याल चलते रहते हैं। ऐसे वक्ति में दिमाग में केवल काम ही भरी रहती है और बुद्धि दूसरा निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए हमारी चेतना की मुख्य जगहों इन्द्रियों, मन और बुद्धि में जैसे ही काम अपना बसेरा डालता है, वहां से ज्ञान गायब हो जाता है। यही वजह है कि बड़े-बड़े ज्ञानियों में भी जब काम उपजता है तो वह उनके ज्ञान को ढक लेता है। काम का मतलब यहां केवल काम-वासना से ही नहीं, बल्कि हमारी अन्य कामनाओं से भी है। कामनाएं या इच्छाएं जीवन भर इंसान का पीछा नहीं छोड़तीं और इस वजह से जीवात्मा का संसार को लेकर मोह बना रहता है।

आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया के चक्कर में फंसी अर्थ -व्यवस्था

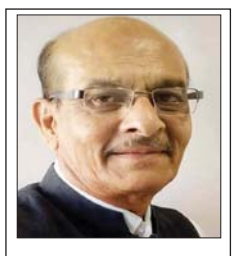

सनत जैन

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आज देश में एक गंभीर बहस चल रही है। एक पक्ष का मानना है, कि 2004 से 2014 के बीच, विशेषकर 2011 तक, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थी। उस दौर में भारत की तुलना चीन, अमेरिका, रुस एवं अन्य यूरोपीय देशों के साथ वैश्विक मंचों पर होने लगी थी। सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों के विस्तार ने देश को नई आर्थिक ऊँचाइयों तक पहुँचाया था। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान जब अमेरिका और यूरोप की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ संकट से जूझ रही थीं, तब भारत अपेक्षाकृत मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ खड़ा दिखाई दिया। अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना था, भारत के विशाल घरेलू बाजार, असंगठित क्षेत्र तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण था, उस समय भारत को वैश्विक आर्थिक क्षेत्र के केंद्र बिन्दू के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन 2011 के बाद भारत का राजनीतिक माहौल तेजी से बदला। भ्रष्टाचार के आरोप, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों तथा अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले जनलोकपाल आंदोलन ने तत्कालीन सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। सरकार की छवि पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें विदेशी ताकतों का हाथ भी बताया जाता है। कारपोरेट जगत भी मनमोहन सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। इस तरह से सारा विपक्ष कांग्रेस और मनमोहन के खिलाफ खड़ा हो गया था। अंततः 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। आलोचकों का आरोप है कि उस समय देश की आडिट रिपोर्ट में लगाए गए कई आर्थिक नुकसान के अनुमान न्यायिक प्रक्रिया में प्रमाणित नहीं हो सके, काल्पनिक आरोपों से तब तक राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका था।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि पिछले एक दशक में ऐसी नीतियाँ अपनाई गईं, जिनसे बड़े कॉर्पोरेट समूहों को लाभ मिला, जबकि लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नोटबंदी, जीएसटी के प्रारंभिक क्रियान्वयन और महामारी के प्रभाव ने छोटे व्यवसायों की कमर तोड़ दी। लाखों सूक्ष्म इकाइयाँ बंद हुईं। रोजगार के अवसर सिमटते चले गए। अर्थ- व्यवस्था में एक अन्य चिंता भारत के बढ़ते आयात और घटती विनिर्माण क्षमता को लेकर है। चीन से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उत्पादों का आयात लगातार बढ़ा है। इसके विपरीत भारत की निर्यात वृद्धि अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई। इससे व्यापार घाटा बढ़ा है। जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता के दावों पर भी प्रश्नचिह्न लगा है। बढ़ती बेरोजगारी, महँगाई और घरेलू ऋण चिंता के विषय बने हुए हैं। किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान कर्जदार और खेती मंहगी होती जा रही है। आम नागरिक की क्रय-शक्ति घट गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न और आवश्यक सेवाएँ लगातार महँगी होती जा रही हैं। दूसरी ओर, शेयर बाजार में तेजी और कॉर्पोरेट मुनाफों के बावजूद आम जनता की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता। इससे आर्थिक विकास और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच का अंतर बढ़ गया है। आम आदमी की आय में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की स्थिति बनी हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक नीतियों का केंद्र केवल बड़े निवेश और कॉर्पोरेट लाभ न होकर रोजगार सृजन, लघु उद्योगों का संरक्षण, कृषि क्षेत्र की मजबूती तथा घरेलू मांग में विस्तार हो। भारत की वास्तविक शक्ति उसके करोड़ों छोटे उद्यमियों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग में निहित है। यदि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँचता, तो ऊँची विकास दर का सपना- सपना बनकर ही रह जायेगा।

भारत के सामने चुनौती केवल विकास दर बढ़ाने की नहीं, बल्कि समावेशी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने की है। आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि भारत वैश्विक दौड़ में आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ता है या फिर अवसरों को खोकर नई चुनौतियों में फंसकर रह जाता है। जिस तरह के हालात वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं वह चिंता बढ़ाने वाले हैं। संवैधानिक संस्थाएं सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। चुनाव आयोग और न्यायपालिका के फैसलों पर आरोपों की झड़ी लग रही है। डॉलर और युआन के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार घटती चली जा रही है। आयात और निर्यात का अंतर बढ़ता चला जा रहा है। जिसके कारण भारत एक ऐसे संकट में फंस गया है, जिससे सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस संकट से देश किस तरह से निकल पाएगा, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की चिंताएं बढी हुई हैं। वर्तमान आर्थिक स्थिति ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चिंता को बढ़ा दिया है।

मालवीय नगर अग्निकांडः मुआवजे से नहीं, जवाबदेही और सुधार से बचेगी ज़िंदगी

डॉ. सत्यवान सौरभ

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में 3 जून 2026 को लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस दर्दनाक हादसे में इक्कीस लोगों की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर ने न केवल राजधानी बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। आग की लपटों से बचने के लिए लोगों को ऊँची इमारत से कूदते हुए देखा गया। सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में प्रसारित हुए दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए अत्यंत पीड़ादायक थे। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी; यह उस व्यवस्था की विफलता का भयावह प्रमाण थी जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।

हर बड़ी दुर्घटना के बाद कुछ दिन तक शोक, संवेदना, जांच और मुआवजे की घोषणाएं होती हैं। फिर धीरे-धीरे मामला सार्वजनिक स्मृति से ओझल हो जाता है। लेकिन मालवीय नगर की यह त्रासदी केवल शोक व्यक्त करके भुला देने योग्य घटना नहीं है। यह उन गहरे संरचनात्मक दोषों की ओर संकेत करती है जो भारत के महानगरों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ और अधिक खतरनाक रूप धारण कर चुके हैं। यह हादसा हमें मजबूर करता है कि हम पूछें–क्या हमारी इमारतें वास्तव में सुरक्षित हैं? क्या अग्नि सुरक्षा नियम केवल कागजों तक सीमित हैं? और क्या प्रशासन की भूमिका केवल दुर्घटना के बाद राहत बांटने तक सीमित रह गई है?

किसी भी बहुमंजिला इमारत में आग लगने की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है–सुरक्षित निकास, अग्निशमन उपकरण और समय पर बचाव। यदि किसी भवन में मौजूद लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनियों से छलांग लगानी पड़े, तो इसका अर्थ है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी थी। आग केवल भवन को नहीं जलाती, वह सुरक्षा संबंधी दावों और प्रशासनिक तैयारियों की वास्तविकता भी उजागर कर देती है। मालवीय नगर की घटना में यही हुआ।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, होटल में कई विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे। यह तथ्य इस त्रासदी को और गंभीर बना देता है। भारत की राजधानी दुनिया भर के पर्यटकों, व्यापारियों और निवेशकों का स्वागत करती है। ऐसे में यदि राजधानी में ही सुरक्षा मानकों की स्थिति इतनी कमजोर हो कि विदेशी नागरिक भी असुरक्षित महसूस करें, तो यह केवल स्थानीय प्रशासन की विफलता नहीं बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी प्रश्नचिह्न है। आधुनिक महानगर की पहचान केवल ऊँची इमारतों और चमकदार होटलों से नहीं होती, बल्कि वहाँ उपलब्ध सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रणाली से होती है।

इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शोक व्यक्त किया तथा मृतकों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। ऐसी संवेदनाएं आवश्यक हैं और संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों को सहायता मिलनी भी चाहिए। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि मुआवजा किसी खोए हुए जीवन को वापस नहीं ला सकता। आर्थिक सहायता दुख की तीव्रता को कम नहीं कर सकती। किसी परिवार का सदस्य, किसी बच्चे का पिता, किसी माता-पिता की संतान या किसी व्यक्ति का जीवनसाथी एक रकम से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए वास्तविक प्रश्न मुआवजे का नहीं, बल्कि रोकथाम का है।

दिल्ली पुलिस द्वारा होटल मालिक के विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया जाना यह संकेत देता है कि जांच एजेंसियां इस घटना को केवल दुर्घटना नहीं मान रही हैं। यदि सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई, अग्निशमन मानकों का पालन नहीं किया गया या भवन निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ, तो यह केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि आपराधिक लापरवाही है। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जवाबदेही के अभाव में नियम केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं।

लेकिन दोष केवल भवन मालिक का नहीं हो सकता। हमें यह भी देखना होगा कि निरीक्षण करने वाले अधिकारी कहाँ थे? क्या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र समय-समय पर नवीनीकृत किए गए थे? क्या किसी निरीक्षण में कमियां सामने आई थीं? यदि आई थीं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि नहीं आई थीं तो क्या निरीक्षण सही तरीके से हुए थे? इन प्रश्नों के उत्तर केवल इस मामले के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहरी प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझने के लिए आवश्यक हैं।

भारत के अधिकांश महानगर आज अव्यवस्थित शहरीकरण की समस्या से जूझ रहे हैं। संकरी गलियां, अवैध निर्माण, क्षमता से अधिक भीड़, पार्किंग की अव्यवस्था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी लगभग हर शहर में सामान्य दृश्य बन चुके हैं। जब तक सब कुछ सामान्य रहता है, तब तक इन कमियों पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन जैसे ही कोई आपदा आती है, यही कमियां जानलेवा साबित होती हैं। मालवीय नगर की तंग गलियों में दमकल वाहनों के पहुंचने में आई कठिनाइयों ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि शहरी योजना और आपदा प्रबंधन के बीच समन्वय का गंभीर अभाव है।

दिल्ली अकेली नहीं है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य महानगर भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अनेक इमारतें ऐसी हैं जहां अग्निशमन यंत्र या तो मौजूद नहीं हैं या वर्षों से उनकी जांच नहीं हुई। आपातकालीन निकास मार्ग अक्सर बंद रहते हैं। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए सुरक्षा मानकों से समझौता कर लेते हैं। दुखद यह है कि कई बार प्रशासन भी इन उल्लंघनों के प्रति उदासीन बना रहता है।नहीं:

अग्नि सुरक्षा केवल भवन निर्माण का तकनीकी विषय नहीं है; यह नागरिक जीवन की रक्षा का मूल आधार है। विकसित देशों में अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन गंभीर अपराध माना जाता है। वहां नियमित निरीक्षण, अनिवार्य मॉक ड्रिल और कठोर दंड व्यवस्था लागू होती है। भारत में भी नियम मौजूद हैं, लेकिन समस्या उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। जब तक नियमों के उल्लंघन पर त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कागजी प्रावधान वास्तविक सुरक्षा में नहीं बदल सकते।

इस त्रासदी ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है–क्या आम नागरिक अग्नि सुरक्षा के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक हैं? अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि आग लगने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। घबराहट, अफवाह और गलत निर्णय अक्सर जान-माल के नुकसान को बढ़ा देते हैं। विद्यालयों, कॉलेजों, कार्यालयों, होटलों और आवासीय परिसरों में नियमित अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण तथा मॉक ड्रिल अनिवार्य किए जाने चाहिए। सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है; यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है।

आवश्यकता इस बात की है कि इस घटना को केवल एक समाचार बनाकर न छोड़ दिया जाए। सभी बहुमंजिला होटलों, गेस्ट हाउसों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। जिन भवनों में नियमों का उल्लंघन पाया जाए, उन्हें तत्काल बंद किया जाए। अग्निशमन विभाग को आधुनिक तकनीक, पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित मानवबल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही स्थानीय निकायों और नगर नियोजन एजेंसियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि भविष्य में आपातकालीन वाहनों को रास्ता मिल सके।

सरकारों को यह समझना होगा कि विकास और सुरक्षा परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। केवल नई इमारतें बनाना विकास नहीं है। सुरक्षित इमारतें बनाना ही वास्तविक विकास है। केवल पर्यटन को बढ़ावा देना पर्याप्त नहीं है; पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। केवल निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण नहीं है; नागरिकों और आगंतुकों के जीवन की रक्षा करना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

मालवीय नगर अग्निकांड एक चेतावनी है। यह चेतावनी केवल दिल्ली के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। यदि आज भी हम नहीं चेते, तो कल किसी अन्य शहर, किसी अन्य होटल, अस्पताल, विद्यालय या आवासीय भवन में इसी तरह की त्रासदी दोहराई जा सकती है। तब फिर वही शोक संदेश होंगे, वही मुआवजे की घोषणाएं होंगी और वही प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे।

मृतकों को वापस नहीं लाया जा सकता। उनके परिवारों की पीड़ा को पूरी तरह कम नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि इस घटना से सबक लेकर सुरक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार किए जाएं, जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए और अग्नि सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाए, तो भविष्य में अनेक जानें बचाई जा सकती हैं। यही इस त्रासदी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

मालवीय नगर की आग ने केवल एक इमारत को नहीं जलाया; उसने हमारी शहरी व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और सुरक्षा संस्कृति की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। अब समय केवल शोक व्यक्त करने का नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई करने का है। क्योंकि हर हादसे के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है–क्या हमने उससे कुछ सीखा? यदि इस बार भी उत्तर नहीं रहा, तो अगली त्रासदी केवल समय का इंतजार कर रही होगी।

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

एक्यूप्रेशर में त्रिधातु पेय की उपयोगिता

चांदी- चांदी पाचनक्रिया से सम्बंधित रोगों को ठीक करती है तथा यह जिगर, आमाशय, अंतड़ियों के बहुत सारे रोगों को भी ठीक करती है। मूत्रप्रणाली से सम्बंधित रोगों को भी चांदी ठीक करती है।

तांबा- तांबा जोड़ों के रोगों, पोलियो, कुष्ठरोग, रक्तचाप से सम्बंधित रोग, घुटने का दर्द, मानसिक तनाव, लकवा तथा पुराने रोगों को ठीक करता है। इन तीनों धातुओं का उपयोग स्त्री, पुरुष, बच्चे-जवान तथा बूढ़े सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा करने के साथ-साथ अगर इन धातुओं से पेय पदार्थ बनाकर इनका उपयोग किया जाए तो रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है।

एक्यूप्रेशर चिकित्सा के द्वारा रोगों को जल्दी ठीक करने के लिए कुछ पेय पदार्थ लिए जाए तो रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पुराने से पुराने रोगों को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर चिकित्सा करने के साथ-साथ रोगी को प्रतिदिन त्रिधातु पेय पिलाया जाए तो रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है तथा इस पेय पदार्थ का सेवन करने से व्यक्ति लम्बी आयु तक स्वस्थ रहता है।

पुराने जमाने में राजा महाराजा सोने-चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे तथा वे मुरब्बों पर सोने तथा चांदी के वरक लगाकर उसको खाते थे। आज भी कई औषधियों तथा मिठाइयों पर सोने-चांदी के वरक लगाए जाते हैं। देखा जाए तो ये सोने और चांदी के वरक अमीरी के परिचालक हैं व स्वास्थ्य के दृष्टि से भी लाभदायक हैं। सभी धातुओं का स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने अलग-अलग गुण होते हैं, जो इस प्रकार हैं-

सोना- सोना श्वास प्रणाली से सम्बंधित रोगों को ठीक करता है जैसे- दमा, फेफड़ों के रोग, सांस फूलना आदि। इसके अलावा यह हृदय तथा मस्तिष्क के रोगों को भी ठीक करता है।

सोना-चांदी-तांबे से पेय बनाने का तरीका

- लगभग एक तौला (10 ग्राम) सोने के सिक्के या गहने या कंगन आदि लें। गहना ऐसा लेना चाहिए, जिसमें कोई मोती या नग न हो जैसे गले की जंजीर।
- लगभग पांच तौला (50 ग्राम) शुद्ध चांदी के सिक्के या कोई चांदी का गहना, जिसमें मोती न लगा हो उसे ले लें।
- लगभग चार तौला (40 ग्राम) शुद्ध तांबे के सिक्के या तांबे का छोटा-सा बर्तन ले लें। यह ध्यान रहे कि बिजली के तार वाला तांबा पेय पदार्थ बनाने के लिए ठीक नहीं होता है।
- इन तीनों धातुओं को सुबह के समय में अच्छी तरह से साफ कर लें तथा किसी स्टील के बर्तन में लगभग 3 प्याले साफ पानी और तीनों धातुओं को डालकर आग पर रखकर उबालें। जब पानी उबलकर एक प्याले के बराबर की मात्रा में रह जाए तो उसे आग से उतार लें। फिर पानी से धातु की वस्तुओं को निकाल लें तथा इसके बाद पानी को साफ कपड़े से छान लें। अब यह पानी उपचार करने के लिए योग्य हो जाता है। इस पेय में रोगों को दूर करने के गुण समाहित हो जाते हैं।
- जब रोगी का उपचार एक्यूप्रेशर चिकित्सा के द्वारा कर रहे हों तथा इसके साथ त्रिधातु का पेय भी रोगी को पीने के लिए दे रहे हों तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खट्टे पदार्थ उस समय न खाएं जैसे नींबू का रस, इमली तथा आम आदि खट्टे पदार्थ। त्रिधातु पेशाब से सम्बंधित रोगों को ठीक करने के लिए काफी फायदेमंद है तथा यह रोगी व्यक्ति को स्वस्थ भी बनाता है। वैसे तो आंवले द्वारा बनाया गया पेय पदार्थ भी स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है।

अति गुणकारी दालचीनी

दालचीनी का उपयोग रोजाना मसालों में सुगन्ध और स्वाद लाने के लिए किया जाता है। यह मुख शुद्धि और कंठ शुद्धि करती है।

- मोटी दालचीनी उष्ण, तीखी, रूक्ष और पित्तकारक है। यह कफ, वायु, खुजली तथा अरुचि का नाश करने वाली एवं हृदय रोग, अर्श, कृमि मिटाने वाली और वीर्यकारक है।
- पतली दालचीनी मधुर, कड़वी, तीखी, सुगंधित, वीर्यवर्धक, शरीर के रंग को निखारने वाली, वायु, पित्त, मुखशोष और तृषा मिटाने वाली है।
- दालचीनी का सेवन करने से अजीर्ण, उल्टी, लार, उदरशूल और अफरा मिटता है। यह स्त्रियों का ऋतुस्राव साफ लाती है और गर्भाशय का संकोचन करती है।
- दालचीनी पानी में पीसकर गर्म करके कनपटी पर लेप करने से अथवा अर्क लगाने से सर्दी के कारण होने वाला सिरदर्द मिटता है।
- दालचीनी, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा पीने से जुकाम दूर होता है।
- दालचीनी का 2-3 बूंद तेल एक कप पानी में मिलाकर पीने से इन्फ्लूएंजा, गृहिणी, आंत्रशूल, हिचकी, उल्टी आदि में काम करता है।
- वैज्ञानिक मतानुसार यह अत्यंत उपयोगी सुगंधित औषधि है। यह उष्ण दीपन, पाचन, वातहर, स्तंभण, गर्भाशय उत्तेजक, गर्भाशय संकोचक एवं शरीर उत्तेजक है। यह जन्तुनाशक है और कालज्वर टाइफाइड तथा अन्य संक्रामक रोगों का नाश करती है एवं उबकाई, उल्टी व अतिसार को मिटाती है।

दालचीनी का तेल उत्तेजक है, अत: यह दांत का शूल, पेट का शूल, जीभ का रुक जाना, जुबान बन्द हो जाना आदि पर गुणकारी है। गरम प्रकृति वालों को दालचीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। दालचीनी के दीर्घकाल तक सेवन करने से नपुंसकता आती है। इसका तेल भी अत्यधिक मात्रा में विषतुल्य है।

पाचन-शक्ति बढ़ाता है

वज्रासन

विधि : बिछे हुए आसन पर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं। पैर के दोनों अंगूठे परस्पर लगे रहें। पैर के तलवों के ऊपर नितम्ब रहे। कमर और पीठ बिलकुल सीधी रहे, दोनों हाथ को कुहनियों से मोड़े बिना घुटनों पर रख दें। हथेलियां नीचे की ओर रहें। दृष्टि सामने स्थिर कर दें। पांच मिनट से लेकर आधे घंटे तक वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन लगाकर भूमि पर लेट जाने से सुप्त वज्रासन होता है।

लाभ : वज्रासन के अभ्यास से शरीर का मध्यभाग सीधा रहता है। श्वास की गति मन्द पड़ने से वायु बढ़ती है। आंखों की ज्योति तेज होती है। वज्रनाड़ी अर्थात वीर्यधारा नाड़ी मजबूत बनती है। वीर्य की ऊर्ध्वगति होने से शरीर वज्र जैसा बनता है। लम्बे समय तक सरलता से यह आसन कर सकते हैं। इससे मन की चंचलता दूर होकर व्यक्ति स्थिर बुद्धिवाला बनता है। शरीर में रक्ताभिसरण ठीक से होकर शरीर निरोगी एवं सुन्दर बनता है। भोजन के बाद इस आसन से बैठने से पाचन शक्ति तेज होती है। कब्ज दूर होता है। भोजन जल्दी हजम होता है। पेट की वायु का नाश होता है। कब्ज दूर होकर पेट के तमाम रोग नष्ट होते हैं। पाण्डुरोग से मुक्ति मिलती है। रीढ़, कमर, जांघ, घुटने और पैरों में शक्ति बढ़ती है। कमर और पैर का वायु रोग दूर होता है। स्मरणशक्ति में वृद्धि होती है। स्त्रियों के मासिक धर्म की अनियमितता जैसे रोग दूर होते हैं। शुक्रदोष, वीर्यदोष, घुटनों का दर्द आदि का नाश होता है। स्नायु पुष्ट होते हैं। स्फूर्ति बढ़ाने के लिए एवं मानसिक निराशा दूर करने के लिए यह आसन उपयोगी है। ध्यान के लिए भी यह आसन उत्तम है। इसके अभ्यास से शारीरिक स्फूर्ति एवं मानसिक प्रसन्नता प्रकट होती है। दिन-प्रतिदिन शक्ति का संचय होता है, इसलिए शारीरिक बल में खूब वृद्धि होती है। काग का गिरना अर्थात गले के टांसिल्स, हड्डियों के पोल आदि स्थानों में उत्पन्न होने वाले श्वेतकण की संख्या में वृद्धि होने से आरोग्य का साम्राज्य स्थापित होता है। फिर व्यक्ति बुखार व सिरदर्द से, कब्ज और मंदाग्नि से या अजीर्ण जैसे छोटे-मोटे किसी भी रोग से पीड़ित नहीं रहता, क्योंकि रोग आरोग्य के साम्राज्य में प्रविष्ट होने का साहस ही नहीं कर पाते।

वज्रासन का अर्थ है बलवान स्थिति। पाचनशक्ति, वीर्यशक्ति तथा स्नायुशक्ति देने वाला होने से यह आसन वज्रासन कहलाता है। इसका ध्यान मूलाधार चक्र में होता है और और श्वास दीर्घ ग्रहण किया जाता है।

दर्द भगाने के कारगर उपाय

जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, उसमें सिरदर्द होना एक आम बात है। लेकिन यह दर्द हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाए तो हमारे लिए बहुत कष्टदायी हो जाता है। दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम पेनकिलर घरेलू उपाय अपनाकर इसे दूर कर सकते हैं। इन घरेलू उपायों के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते।

अदरक
अदरक एक दर्द निवारक दवा के रूप में भी काम करती है। यदि सिरदर्द हो रहा हो तो सूखी अदरक को पानी के साथ पीसकर उसका पेस्ट बना लें और इसे अपने माथे पर लगाएं। इसे लगाने पर हल्की जलन जरूर होगी, लेकिन यह सिरदर्द दूर करने में मददगार होती है।

सोडा
पेट में दर्द होने पर कप पानी में एक चुटकी खाने वाला सोड़ा डालकर पीने से पेट दर्द में राहत मिलती है। स्त्रियों के मासिक धर्म के समय पेट के नीचे होने वाले दर्द को दूर करने में खाने वाला सोड़ा पानी में मिलाकर पीने से दर्द दूर होता है।
एसिडिटी होने पर एक चुटकी सोड़ा, आधा चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा, 8 बूंदे नींबू का रस और स्वादानुसार नमक पानी में मिलाकर पीने से एसिडिटी में राहत मिलती है।

अजवायन
सिरदर्द होने पर एक चम्मच अजवायन को भूनकर साफ सूती कपड़े में बांधकर नाक के पास लगाकर गहरी सांस लेने से सिरदर्द में राहत मिलती है। ये प्रक्रिया तब तक दोहराएं, जब तक आपका सिरदर्द ठीक नहीं हो जाता। पेटदर्द को दूर करने में भी अजवायन सहायक होती है। पेटदर्द होने पर आधा चम्मच अजवायन को पानी के साथ फांखने से पेटदर्द में राहत मिलती है।

बर्फ
सिरदर्द में बर्फ की सिंकाई करना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस में भी बर्फकी सिंकाई लाभदायक होती है। गर्दन में दर्द होने पर भी बर्फ की सिंकाई लाभदायक होती है।

हल्दी
हल्दी कीटाणुनाशक होती है। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और दर्द निवारक तत्व पाए गए हैं। ये तत्व चोट के दर्द और सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। घाव पर हल्दी का लेप लगाने से वह ठीक हो जाता है। चोट लगने पर दूध में हल्दी डालकर पीने से दर्द में राहत मिलती है। एक चम्मच हल्दी में आधा चम्मच काला गर्म पानी के साथ फांखने से पेट दर्द व गैस में राहत मिलती है।

तुलसी के पत्ते
तुलसी में बहुत सारे औषधीय तत्व पाए जाते हैं। तुलसी की पत्तियों को पीसकर चंदन पाउडर में मिलाकर पेस्ट बना लें। दर्द होने पर प्रभावित जगह पर उस लेप को लगाने से दर्द में राहत मिलेगी। एक चम्मच तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाकर हल्का गुनगुना करके खाने से गले की खराश और दर्द दूर हो जाता है। खांसी में भी तुलसी का रस काफी फायदेमंद होता है।

मैथी
एक चम्मच मेथी दाना में चुटकी-भर पिसी हुई हींग मिलाकर पानी के साथ फांखने से पेटदर्द में आराम मिलता है। मैथी डायबिटीज में भी लाभदायक होती है। मैथी के लड्डू खाने से जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है।

हींग
हींग दर्द निवारक और पित्तवर्द्धक होती है। छाती और पेटदर्द में हींग का सेवन लाभकारी होता है। छोटे बच्चों के पेट में दर्द होने पर हींग को पानी में घोलकर पकाने और उसे बच्चों की नाभि के चारों ओर उसका लेप करने से दर्द में राहत मिलती है।

सेब
सुबह खाली पेट प्रतिदिन एक सेब खाने से सिरदर्द की समस्या से छुटकारा मिलता है। चिकित्सकों का मानना है कि सेब का नियमित सेवन करने से रोग नहीं घेरते।

करेला
करेले का रस पीने से पित्त में लाभ होता है। जोडों के दर्द में करेले का रस लगाने से काफी राहत मिलती है।

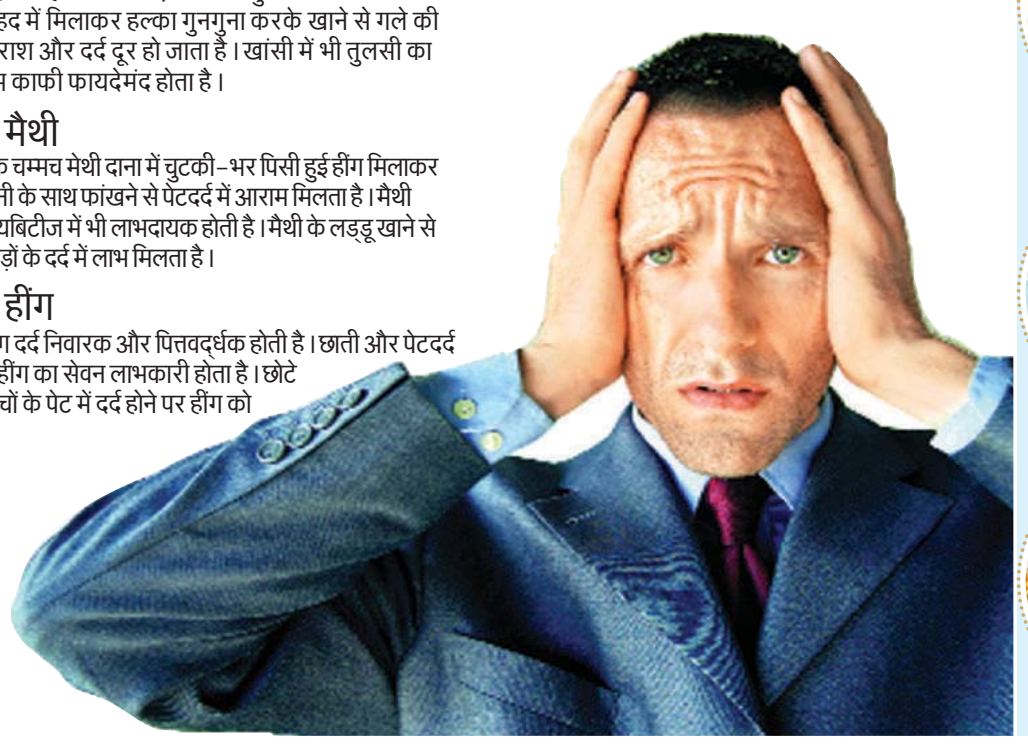

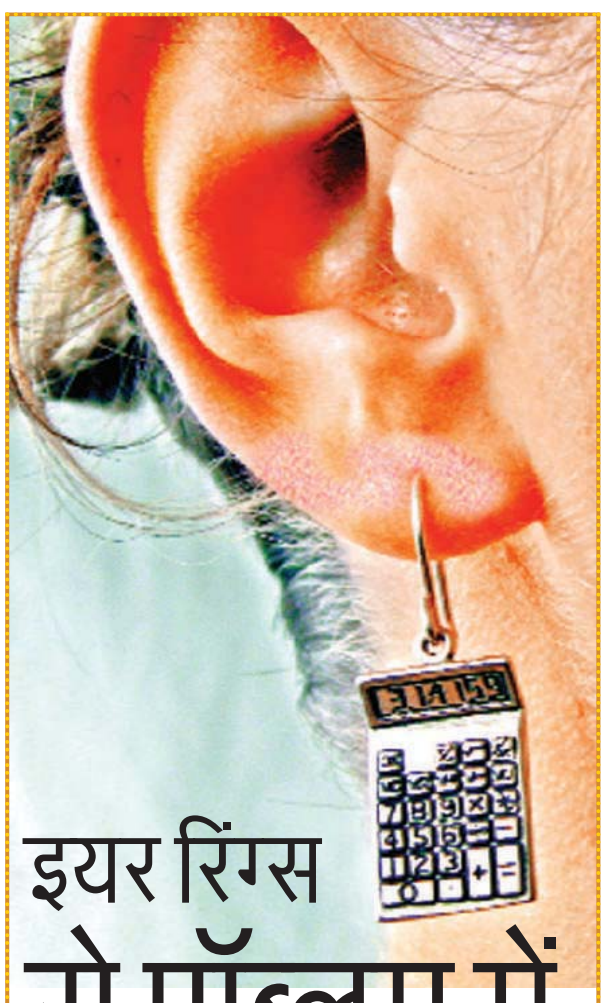

इयर रिंग्स से प्रॉब्लम में आजमाएं

कानों में बालियां और झुमके पहनना कौन लड़की नहीं चाहती। लेकिन कभी-कभी लगातार इयर रिंग्स पहनने से कान के छेद में खुजली, दाने या सूजन आ जाती है। जानती हैं इसकी वजह क्या होती है? आपके कान की बाली में मौजूद निकिल की वजह से ऐसा होता है। इसका एक खास इलाज है। अपने कान से बालियां निकालकर कान के छेद को हाइड्रोजन पैराऑक्साइड से धोएं। यही नहीं, कानों को एलर्जी से बचाने के लिए हमेशा सोने या चांदी की बालियां पहनें या फिर कान की तली में नेल पॉलिश का एक कोट लगाकर पहनें। इससे न तो आपको कान में घाव होगा और न ही दाने होंगे।

एक प्रण ऐसा भी... 388 दिनों की नंगे पैर 'तपस्या'

आखिर दिलाई बालोतरा को जिले की सौगात

सत्ता को झुकाने वाली जिद : पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत के जनसंघर्ष की वो दास्तान, जो इतिहास बन गई, ठुकरा दी थीं सीएम की डिनर पार्टी

मनोहरसिंह खोखर। जयपुर

राजस्थान की राजनीति में कई नेता अपने बयानों और सियासी दांव-पेंच के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर-बालोतरा क्षेत्र में एक ऐसा राजनेता भी है जिसकी पहचान जनता के प्रति कड़े संकल्प और उग्र जनसंघर्ष से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं पचपदरा विधानसभा सीट से दो बार कांग्रेस के विधायक रहे मदन प्रजापत की। क्षेत्र के लोग उन्हें विकास पुरुष से ज़्यादा एक ऐसे 'जिद्दी जननायक' के रूप में देखते हैं, जिन्होंने जनता की 40 साल पुरानी मांग को मनवाने के लिए खुद को बेहद कड़े इम्तिहान में झोंक दिया। पूर्व विधायक मदन प्रजापत की कहानी एक राजनेता के अनोखे और कड़े संकल्प की दास्तां है। उन्हें राजनीति में उनके विकास कार्यों से ज़्यादा 'बालोतरा को जिला बनाने के लिए नंगे पैर रहने के ऐतिहासिक प्रण' के लिए जाना जाता है। मदन प्रजापत की यह कहानी दर्शाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि किसी जनप्रतिनिधि के भीतर अपनी जनता की मांग को लेकर सच्ची जिद और जनभावनाओं के प्रति समर्पण हो, तो वह सरकार को भी झुकने पर मजबूर कर सकता है। उनका यह सफरनामा राजस्थान की सियासत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।

कुर्सी भले गई, पर दिलों पर राज

बालोतरा की जनता आज भी मानती है मदन प्रजापत को अपना **'भागीरथ'**

विधानसभा के बाहर त्यागे जूते और ली स्वः शपथ

मदन प्रजापत की कहानी का सबसे स्वर्णिम अध्याय 23 फरवरी 2022 को राजस्थान विधानसभा के गेट नंबर 5 के बाहर से शुरू हुआ। राज्य सरकार के बजट में जब बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा नहीं हुई, तो प्रजापत ने वहीं अपने जूते-चप्पल त्याग दिए। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाता, वे पैर में कुछ नहीं पहनेंगे। इसके बाद शुरू हुआ 388 दिनों का एक बेहद कठिन सफर। थार मरुस्थल की चुभती हुई 48 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी हो, हाड़ कंपाने वाली सर्दी या फिर बरसात की सड़कों की कीचड़। मदन प्रजापत हर जगह नंगे पैर ही जनता के बीच नजर आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने राजस्थान में सैंकड़ों किलोमीटर का सफर नंगे पांव ही तय किया। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया भी हुआ। जयपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक डिनर पार्टी के दौरान कुछ अन्य विधायकों ने मदन प्रजापत से कहा कि आज सीएम खुद अपने हाथों से उन्हें जूते पहनाएंगे। प्रजापत को डर था कि कहीं उनकी प्रतिज्ञा अधूरी न रह जाए, इसलिए वे बिना भोजन किए ही उस पार्टी से चुपचाप हाथ जोड़कर बाहर निकल आए। आखिरकार 17 मार्च 2023 को उनकी यह 'तपस्या' रंग लाई और सरकार को बालोतरा को नए जिले के रूप में घोषित करना पड़ा। इसके बाद उनके समर्थकों ने 750 ग्राम चांदी की जूतियां बनवाईं, जिसे मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उन्हें पहनाकर उनका संकल्प पूरा कराया गया।

जनता के हक के लिए गए जेल, बालोतरा में हुआ था भारी बवाल -

मदन प्रजापत की कहानी सिर्फ नंगे पैर चलने के अहिंसक संकल्प तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनका राजनीतिक जीवन उग्र आंदोलनों और जेल यात्रा का भी गवाह रहा है। साल 2016 का 'रीको थप्पड़ कांड' उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। जून 2016 में बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने मौके पर पहुंचकर इस कार्रवाई को गरीब विरोधी और भेदभावपूर्ण बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसी दौरान अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस हो गई और रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक (RM) प्रवीन गुप्ता को थप्पड़ मारने का आरोप मदन प्रजापत पर लगा। पुलिस ने जब उन्हें रेलवे फाटक के पास से धरने के दौरान गिरफ्तार किया, तो पूरे बालोतरा में भारी बवाल मच गया। उग्र समर्थकों और पुलिस के बीच लाठी-भाटा जंग हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए और गाड़ियों में आगजनी तक की गई। इस मामले में मदन प्रजापत को जमानत नहीं मिली और उन्हें करीब एक महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। हालांकि, बाद में बालोतरा की एसीजेएम कोर्ट ने ठोस सबूतों के अभाव में उन्हें और उनके समर्थकों को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया।

राजनीतिक उतार-चढ़ाव का दौर -

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर मदन प्रजापत ने पचपदरा विधानसभा सीट से दो बार चुनाव जीता। विधानसभा में वे हमेशा मुखर रहे। चाहे स्थानीय रिफाइनरी में स्थानीय युवाओं को रोजगार का मुद्दा हो या फिर अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोलना, वे लगातार जनता के बीच बने रहे। हालांकि, साल 2023 के विधानसभा चुनाव में वे अपनी सीट नहीं बचा पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चुनावी हार के बावजूद बालोतरा को जिला मुख्यालय का दर्जा दिलाने वाले 'नायक' के रूप में क्षेत्र के लोग आज भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं।

हार तात्कालिक, प्रभाव दूरगामी -

पश्चिमी राजस्थान की सियासत में हार-जीत के आंकड़े अक्सर बदलते रहते हैं, लेकिन जनता के दिलों पर छोड़ी गई छाप अमिट होती है। पचपदरा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक मदन प्रजापत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 23 फरवरी 2022 को राजस्थान विधानसभा के गेट नंबर 5 के बाहर अपने जूते-चप्पल त्यागने वाले मदन प्रजापत ने 388 दिनों तक थार की झुलसाती धूप और कड़कड़ाती ठंड में नंगे पैर रहकर बालोतरा को जिला तो दिलवा दिया, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि, चुनावी हार के ढाई साल बाद आज जब बालोतरा एक स्वतंत्र जिले के रूप में पूरी तरह स्थापित हो चुका है, तब यहां की जनता की राय और इस संघर्ष के दूरगामी राजनीतिक प्रभाव एक नई कहानी बयां कर रहे हैं।

जनता की मौजूदा रायः कुर्सी भले गई, पर हमारे दिलों के भागीरथ

बालोतरा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आज भी मदन प्रजापत के इस त्याग को लेकर गहरी कृतज्ञता का भाव है। स्थानीय व्यापारियों, युवाओं और बुजुर्गों का मानना है कि बालोतरा को जिला बनवाना किसी बड़े सपने के सच होने जैसा था। कलेक्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय और अन्य जिला स्तरीय सुविधाओं का लाभ उठा रही जनता आज खुलकर कहती है, 'चुनाव में समीकरण अलग होते हैं, जातिगत गणित और एंटी-इन्कम्बेंसी की वजह से मदन जी चुनाव हार गए, लेकिन बालोतरा के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में रहेगा। पैर के छालों की कीमत वोटों से नहीं आंकी जा सकती।' जनता उन्हें आज भी बालोतरा का 'भागीरथ' मानती है।

'अंडरकरेंट' जो बदल सकता है भविष्य का समीकरण

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मदन प्रजापत की यह हार तात्कालिक थी, लेकिन इस संघर्ष के दूरगामी प्रभाव बहुत गहरे हैं। भले ही मदन प्रजापत आज विधानसभा में नहीं हैं, लेकिन बाड़मेर-बालोतरा और पूरे पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में उनका कद अपनी पार्टी (कांग्रेस) के कई मौजूदा विधायकों से कहीं अधिक बड़ा हो चुका है। पिछले चुनावों में जो कसर रह गई थी, वह अब धीरे-धीरे जनता के भीतर एक 'अंडरकरेंट' (अंतःप्रवाह) के रूप में बदल रही है। क्षेत्र के लोगों में एक टीस है कि जिला पाने के बाद भी उन्होंने उस नेता को हरा दिया जिसने अपनी देह को कष्ट दिया। यह सहानुभूति भविष्य के चुनावों में कांग्रेस के लिए एक मजबूत ढाल और मदन प्रजापत के लिए 'ब्याज समेत' सियासी लाभ का जरिया बन सकती है। बालोतरा जिला बनने का पूरा श्रेय आज भी मदन प्रजापत के खाते में ही जाता है। ऐसे में आगामी राजनीतिक दौरों, स्थानीय निकाय चुनावों या भविष्य के विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे की गूंज कम नहीं होने वाली। भाजपा के लिए भी इस क्षेत्र में मदन प्रजापत के इस 'इमोशनल कार्ड' और जनता के जुड़ाव की काट ढूंढना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादक: नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालाना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)